संख्या-75/2018/1340/52-1-2018-01(123)/13

प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 16 अगस्त, 2018

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 21 एवं 27.07.2015 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 99वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद अमेठी के वि0ख0-सिंहपुर, बहादुरपुर, जगदीशपुर तथा वि0ख0-शुकुल बाजार में राजकीय आई०टी०आई० के भवन निर्माण हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(24)/2013-पी0पी0, दिनांक 31.08.2015 द्वारा जनपद अमेठी की प्रश्नगत आई0टी0आई0 भवनों के निर्माण के लिए पी0एफ0ए0डी0 के अनुसार कुल अनुमोदित लागत रू0 3252.77 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0** (पूर्व नाम **उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0)** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये भारत सरकार द्वारा कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष **प्रथम किश्त** के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) एवं पी0एफ0ए0डी0 के अनुसार उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू० 626.385 लाख (रूपये छः करोड़ छब्बीस लाख अड़तीस हजार पांच सौ मात्र) अर्थात् कुल रू० 1626.385 लाख (रूपये सोलह करोड़ छब्बीस लाख अड़तीस हजार पांच सौ मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजट रू0 4000.00 लाख में से निम्नानुसार अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	पी.एफ.ए.डी. द्वारा इकाई लागत	भा0स0 द्वारा कुल अनुमोदित केन्द्रांश	पी.एफ.ए.डी. के अनुसार कुल राज्यांश (5-6)	पी.एफ.ए.डी. द्वारा अनुमोदित कुल लागत	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित **प्रथम किश्त**		कुल प्रस्तावित धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**अमेठी**	वि०ख०-सिंहपुर के इन्होना में रा0 आई0 टी0 आई0 का निर्माण	01	780.38	500.00	280.38	780.38	250.00	140.19	390.19

http://shasanadesh.up.nic.in

2	तदैव	वि०ख०-बहादुरपुर के तेंदुआ में रा0 आई0टी0आई0 का निर्माण	01	782.40	500.00	282.40	782.40	250.00	141.20	391.20
3	तदैव	वि०ख०-जगदीशपुर के कठौरा में रा0 आई0टी0आई0 का निर्माण	01	887.48	500.00	387.48	887.48	250.00	193.74	443.74
4	तदैव	वि०ख०-शुकुल बाजार के सत्थिन में रा0 आई0टी0 आई0 का निर्माण	01	802.51	500.00	302.51	802.51	250.00	151.255	401.255
		योग			**2000.00**	**1252.77**	**3252.77**	**1000.00**	**626.385**	**1626.385**

2- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोंदित लागत से समयान्तर्गत गुणवत्ता सहित निर्माण कार्य 36 माह में पूरा कर लिया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन अनुमन्य नहीं होगा । निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के अधिशाषी अभियन्ता, सुल्तानपुर तथा प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गौरीगंज अमेठी के मध्य किये गये त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) की शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(5)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है ।

(6)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7)- कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आई०टी०आई० के भवन निर्माण का मानक एवं डिजाइन वही होगी, जो केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है।

(8)- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

(9)- जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्माणाधीन आई०टी०आई० के भवन निर्माण की गुणवत्ता की जॉच करायी जायेगी, ताकि निर्माण कार्य अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण हों। अवमुक्त धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स एवं ग्रामों/स्थलों की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र एवं उक्त अन्य अभिलेख दो-दो प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(10)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक स्थायी बोर्ड भी बनवाया जायेगा जिस पर योजना के स्वीकृति की तिथि, वित्तीय स्रोत, योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि अंकित होगी।

(11)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ताकी पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित

http://shasanadesh.up.nic.in

कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

(12)- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाया।

(13)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से मानचित्रों को स्वीकृत कराया जायेगा तथा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(14)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 ( ) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(15)- वांछित धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खातों आदि में नहीं रखा जायेगा।

(16)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30.03.2018 (यथा संशोधित) 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(18)- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-**0105-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण (के0 60/रा0 40-के0)-24-वृहद निर्माण कार्य** के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-234/दस-2018, दिनांक 14.08.2018 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

Unicode ITI G.O

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1340(1)/बावन-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत आई०टी०आई० के भवन निर्माण का मानकानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यों के लिए किसी दूसरी मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।
6- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 रोजगार भवन, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।
7- निदेशक, **उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आई०टी०आई० के भवन के निर्माण का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अमेठी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत आई०टी०आई० के भवन निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
13- वित्त(आय-व्ययक)अनु0-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in